

21वीं सदी में अमेरिका-चीन संबंधों की बदलती गतिशीलता: सहयोग या संघर्ष?

Yachika, Research Scholar, Department of Social Science (Political Science), Faculty of Humanities and Liberal Education, Baba Mastnath University, Rohtak, Haryana

शोध सार

यह शोधपत्र 21वीं सदी में अमेरिका-चीन संबंधों की उभरती प्रकृति का पता लगाता है, तथा यह आकलन करता है कि क्या यह प्रक्षेपवक्र रणनीतिक सहयोग या तीव्र संघर्ष का पक्षधर है। जबकि आर्थिक अंतरनिर्भरता ने शुरू में एक स्थिर संबंध को आधार प्रदान किया, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सैन्य प्रभाव और वैश्विक मानदंडों पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने उनके संबंधों को तेजी से परिभाषित किया है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य रुख और कूटनीतिक जुड़ाव जैसे प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण करके शोधपत्र उन ताकतों का मूल्यांकन करता है जो दोनों देशों को प्रतिद्वंद्विता या सहयोग की ओर धकेल रही हैं। निष्कर्ष अभिसरण और विचलन के एक जटिल परस्पर क्रिया का सुझाव देते हैं, जो दर्शाता है कि अमेरिका-चीन संबंध न तो पूरी तरह से सहयोगात्मक हैं और न ही अनिवार्य रूप से संघर्षपूर्ण हैं, बल्कि भू-राजनीतिक, आर्थिक और घरेलू विचारों में बदलाव के द्वारा आकार लेते हैं।

संकेत शब्द :

अमेरिका-चीन संबंध, सामरिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक अंतरनिर्भरता, हिंद-प्रशांत, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा, व्यापार युद्ध, सुरक्षा दुविधा, बहुपक्षीय कूटनीति, आधिपत्य, भू-राजनीतिक तनाव

1. परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध वैश्विक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। एक समय में सतर्क जुड़ाव और पारस्परिक आर्थिक लाभ के लिए चिह्नित, यह तेजी से एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल गया है। एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय और अमेरिका के नेतृत्व वाली उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसकी चुनौती ने वैश्विक स्थिरता के भविष्य को लेकर चिंताएँ पैदा की हैं। यह पेपर अमेरिका-चीन संबंधों में बदलती गतिशीलता का विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि क्या संबंध स्थायी संघर्ष या सशर्त सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और रणनीतिक बदलाव

पिछले आधी सदी में अमेरिका-चीन संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो सतर्क जुड़ाव से लेकर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तक विकसित हुए हैं। इस रिश्ते की ऐतिहासिक जड़ें शीत युद्ध के दौर में देखी जा सकती हैं, जब अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रति संतुलन के रूप में चीन के प्रति अपना रुख बदल दिया था। 1972 में निक्सन-माओ शिखर सम्मेलन ने एक कूटनीतिक सफलता को चिह्नित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1979 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर और डेंग शियाओपिंग के तहत संबंधों का सामान्यीकरण हुआ। यह जुड़ाव वैचारिक संरेखण के बजाय पारस्परिक रणनीतिक लाभ की यथार्थवादी समझ पर आधारित था (Kissinger, 2011)।

1980 और 1990 के दशक के दौरान, द्विपक्षीय संबंध मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग और वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चीन के एकीकरण पर केंद्रित थे। इसकी परिणति 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के प्रवेश के रूप में हुई, जो एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने चीन को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति और आर्थिक प्रतिस्पर्धी के रूप में तेजी से उभरने में मदद की (Shambaugh, 2013)। इस स्तर पर, अमेरिकी नीति इस विश्वास से निर्देशित थी कि आर्थिक उदारीकरण अंततः चीन में राजनीतिक सुधार की ओर ले जाएगा - जिसे अक्सर "सगाई रणनीति" (Friedberg, 2011) के रूप में संदर्भित किया जाता है।

हालाँकि, 21वीं सदी की शुरुआत में वाशिंगटन में यह अहसास बढ़ रहा था कि चीन का उदय उदार लोकतंत्रों के साथ राजनीतिक अभिसरण की ओर नहीं ले जा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में, चीन ने एक अधिक मुखर विदेश नीति अपनाई, जिसमें "राष्ट्रीय कायाकल्प" पर जोर दिया गया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार किया गया। इसने, बढ़े हुए सैन्य खर्च और राजनीतिक केंद्रीकरण के साथ मिलकर, अमेरिका की रणनीतिक धारणा को भागीदार से प्रतिद्वंद्वी में बदल दिया (Mastro, 2019)।

ट्रम्प प्रशासन के समय तक, अमेरिकी नीति स्पष्ट रूप से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ गई थी, जैसा कि 2017 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में परिलक्षित होता है, जिसने चीन को एक "संशोधनवादी शक्ति" के रूप में पहचाना जो अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना चाहता है। बिडेन प्रशासन ने बड़े पैमाने पर इस ढांचे को जारी रखा है, हालाँकि गठबंधन-निर्माण और कूटनीति पर अधिक जोर दिया है। ये बदलाव संकेत देते हैं कि अमेरिका-चीन संबंध अब केवल आर्थिक जुड़ाव से नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में व्यापक वैचारिक, तकनीकी और सैन्य प्रतिस्पर्धा से प्रेरित हैं (Allison, 2017; Rolland, 2020)।

3. आर्थिक अंतरनिर्भरता और व्यापार संघर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को लंबे समय से गहरी निर्भरता और पारस्परिक लाभ के रूप में वर्णित किया गया है, फिर भी यह 21वीं सदी में तनाव और रणनीतिक घर्षण का एक प्रमुख स्रोत भी बन गया है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन के प्रवेश के बाद, द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से विस्तार हुआ। 2019 तक, चीन वस्तुओं में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, जबकि अमेरिका चीन के शीर्ष निर्यात बाजारों में से एक बना रहा (Morrison, 2019)। आर्थिक पूरकता - जहां अमेरिका ने कम लागत वाली वस्तुओं का आयात किया और चीन को पूंजी और प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई - ने शुरू में सहयोग के तर्क को मजबूत किया।

हालांकि, समय के साथ, व्यापार असंतुलन, बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार पहुंच बाधाओं पर चिंताएं विवादास्पद बिंदुओं के रूप में उभरीं। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा, जो 2010 के दशक के मध्य तक 300 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया था, को न केवल एक आर्थिक मुद्दे के रूप में देखा जाने लगा, बल्कि अमेरिकी उद्योग और नौकरियों के लिए एक खतरे के रूप में भी देखा जाने लगा (Bown & Kolb, 2021)। ये चिंताएँ 2018 में ट्रम्प प्रशासन के तहत शुरू किए गए यूएस-चीन व्यापार युद्ध में परिणत हुईं, जिसमें सैकड़ों बिलियन डॉलर के सामान पर एक जैसे टैरिफ लगाए गए।

व्यापार युद्ध ने आर्थिक अंतरनिर्भरता की नाजुकता को उजागर किया। जनवरी 2020 में हस्ताक्षरित "चरण एक" समझौते का उद्देश्य कुछ विवादों को हल करना था - जैसे कि चीन द्वारा अमेरिकी आयात बढ़ाने और बौद्धिक संपदा की रक्षा करने की प्रतिज्ञा - कई संरचनात्मक मुद्दे अनसुलझे रहे (यूएसटीआर का कार्यालय, 2020)। इसके अलावा, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र (जैसे, अर्धचालक, 5 जी, दुर्लभ पृथ्वी) में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को अलग करने के अमेरिकी प्रयासों ने द्विपक्षीय आर्थिक प्रतिमान में अंतरनिर्भरता से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा (Segal, 2020) की ओर एक गहरा बदलाव दर्शाया।

कोविड-19 महामारी और उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने अमेरिका के भीतर उत्पादन को "पुनः स्थापित" करने और चीनी विनिर्माण पर निर्भरता कम करने के आह्वान को और तेज़ कर दिया है। दूसरी ओर, चीन अपनी "दोहरी परिसंचरण" रणनीति को बढ़ावा दे रहा है, जो बाहरी व्यापार निर्भरता पर आत्मनिर्भरता और घरेलू खपत पर जोर देती है (He, 2021)। ये घटनाक्रम बताते हैं कि आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अमेरिका-चीन आर्थिक जुड़ाव की प्रकृति अधिक चयनात्मक, रणनीतिक और प्रतिभूतिकृत होती जा रही है।

4. सुरक्षा और सैन्य प्रतिस्पर्धा

अमेरिका-चीन संबंधों का सुरक्षा और सैन्य आयाम सतर्कतापूर्ण जुड़ाव से खुली रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल गया है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में। जैसे-जैसे चीन की सैन्य क्षमताएँ परिष्कार और पहुँच दोनों में बढ़ रही हैं, अमेरिका इन घटनाक्रमों को पूर्वी एशिया और व्यापक प्रशांत क्षेत्र में अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखता है। इस प्रतिद्वंद्विता के केंद्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का आधुनिकीकरण अभियान है, जिसका उद्देश्य मध्य शताब्दी तक चीन को "विश्व स्तरीय सेना" में बदलना है (रक्षा सचिव का कार्यालय, 2023)।

इस रणनीतिक प्रतियोगिता में प्राथमिक फ्लैशपॉइंट्स में से एक दक्षिण चीन सागर है, जहाँ चीन ने विशाल क्षेत्रीय दावों का दावा किया है, कृत्रिम द्वीप बनाए हैं, और प्रमुख चौकियों का सैन्यीकरण किया है। इन कार्रवाइयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अधिकारों का दावा करने के लिए नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता (FONOPs) को बनाए रखता है। अमेरिका और उसके सहयोगी चीन के व्यवहार को संशोधनवादी और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर करने वाला मानते हैं (Kaplan, 2014; Buszynski & Sazlan, 2007)।

तनाव का एक और प्रमुख क्षेत्र ताइवान है, जिसे चीन एक अलग प्रांत के रूप में देखता है। अमेरिका, "वन चाइना" नीति का पालन करते हुए, ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है, जिसमें हथियारों की बिक्री और सैन्य सहयोग बढ़ाना शामिल है। इस क्षेत्र में गलत अनुमान या वृद्धि की संभावना अधिक है, खासकर ताइवान के क्षेत्र के पास चीन की बढ़ती हवाई और नौसैनिक घुसपैठ को देखते हुए (Glaser, 2021)। ताइवान का मुद्दा एक "फ्लैशपॉइंट" बना हुआ है, जिसमें सीधे यूएस-चीन सैन्य संघर्ष को ट्रिगर करने की क्षमता है।

पारंपरिक सैन्य चिंताओं के अलावा, दोनों देश साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सरकार और कॉर्पोरेट नेटवर्क को निशाना बनाने सहित चीन की साइबर जासूसी गतिविधियों ने आपसी संदेह को और बढ़ा दिया है (Rolland, 2020)। इसके साथ ही, दोनों देश हाइपरसोनिक हथियारों, मानव रहित प्रणालियों और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे अस्पष्ट नियमों के साथ हथियारों की दौड़ में योगदान मिल रहा है।

अमेरिकी इंडो-पैसिफिक रणनीति और चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला के लिए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण को दर्शाती है। जबकि अमेरिका का लक्ष्य चीनी प्रभाव को रोकने के लिए गठबंधनों और साझेदारियों का एक नेटवर्क बनाए रखना है, चीन एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है जो अमेरिकी प्रभुत्व को कम करता है (White, 2012)। ये विरोधी ढाँचे प्रत्यक्ष टकराव नहीं तो लगातार रणनीतिक घर्षण की संभावना को बढ़ाते हैं।

5. प्रौद्योगिकी और वैचारिक प्रतिद्वंद्विता

21वीं सदी में अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता को तकनीकी वर्चस्व और वैचारिक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देश वैश्विक मानदंडों, मानकों और शासन संरचनाओं को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तकनीकी प्रतियोगिता के केंद्र में उभरती हुई तकनीकों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 5 जी दूरसंचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में नेतृत्व की दौड़ है - ऐसे क्षेत्र जिन्हें व्यापक रूप से आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है (Allen, 2019)।

अमेरिका ने चीन के राज्य-नेतृत्व वाले नवाचार मॉडल पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें भारी सरकारी सब्सिडी, रणनीतिक योजना (जैसे, *मेड इन चाइना 2025*) और औद्योगिक जासूसी शामिल है। वाशिंगटन का तर्क है कि हुवावे और जेडटीई जैसी चीनी कंपनियाँ, जो सरकार की नज़दीकी निगरानी में काम कर रही हैं, वैश्विक संचार बुनियादी ढांचे पर संभावित निगरानी और नियंत्रण के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पेश करती हैं (Rühlig, 2020)। नतीजतन, अमेरिका ने निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं और उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी तक चीन की पहुँच को प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, जिसमें चीनी तकनीकी फर्मों को ब्लैकलिस्ट करना और सहयोगियों पर मुकदमा चलाने का दबाव डालना शामिल है (Lee & Triolo, 2020)।

चीन, बदले में, इन कार्रवाइयों को अपने उदय को रोकने और अमेरिकी तकनीकी प्रभुत्व को बनाए रखने के प्रयासों के रूप में देखता है। जवाब में, बीजिंग ने तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयासों को तेज कर दिया है, अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग में अरबों का निवेश किया है और भविष्य के वैश्विक तकनीकी मानकों को आकार देने के लिए चीन मानक 2035 पहल जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं (Kania & Weber, 2020)।

तकनीकी दौड़ के समानांतर सत्तावादी राज्य पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के बीच वैचारिक प्रतिस्पर्धा है। चीन अपने मॉडल को अधिक कुशल और तेजी से विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए बेहतर रूप से अनुकूल के रूप में प्रस्तुत करता है, खासकर ग्लोबल साउथ में। दूसरी ओर, अमेरिका इस प्रतिस्पर्धा को लोकतांत्रिक मूल्यों, डिजिटल स्वतंत्रता और खुले इंटरनेट (Polyakova & Meserole, 2019) को संरक्षित करने के संघर्ष के रूप में देखता है।

यह वैचारिक विभाजन वैश्विक शासन संस्थाओं में भी दिखाई देता है, जहाँ दोनों देश अक्सर प्रतिस्पर्धी आख्यान और ढाँचे प्रस्तावित करते हैं - उदाहरण के लिए, चीन की "साइबर संप्रभुता" बनाम अमेरिका की खुले, वैश्विक इंटरनेट की वकालत। इसलिए तकनीकी और वैचारिक प्रतिस्पर्धा केवल बुनियादी ढाँचे या

प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों और मूल्यों को कौन परिभाषित करेगा।

6. राजनयिक जुड़ाव और बहुपक्षीय तनाव

21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक जुड़ाव सतर्क सहयोग और रणनीतिक टकराव के बीच उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जो वैश्विक प्रभाव के लिए उनकी व्यापक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। जबकि द्विपक्षीय कूटनीति ने संघर्ष प्रबंधन और मुद्दे-आधारित सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, बहुपक्षीय क्षेत्र तेजी से विवादास्पद हो गया है, जिसमें दोनों शक्तियां अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में मानक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

अमेरिका-चीन रणनीतिक और आर्थिक वार्ता जैसे मंच व्यापार, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर आपसी समझ और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण चैनल के रूप में काम करते थे। हालाँकि, बढ़ते तनावों के बीच ये संवाद पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुए हैं, खासकर ट्रम्प प्रशासन के दौरान, जिसने कूटनीति के लिए अधिक टकरावपूर्ण और लेन-देन वाला दृष्टिकोण अपनाया (Wang, 2021)। बिडेन प्रशासन, कुछ स्थिरता की मांग करते हुए, संबंधों को लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करना जारी रखता है, गठबंधन और साझेदारी के महत्व पर जोर देता है (White House, 2021)।

संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाओं में तनाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अमेरिका चीन पर अपने बढ़ते आर्थिक प्रभाव का उपयोग वैश्विक शासन संरचनाओं में हेरफेर करने और सत्तावादी मानदंडों को आगे बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगाता है, जबकि चीन अमेरिकी आलोचना को अपनी वैधता और विकास मॉडल को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखता है (Suzuki, 2022)। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, ट्रम्प प्रशासन के डब्ल्यूएचओ से हटने और प्रकोप से निपटने के लिए चीन को दोषी ठहराने के फैसले ने गहरी कूटनीतिक दरारों को उजागर किया (Kickbusch & Liu, 2020)।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसी संस्थाओं के माध्यम से अपने बहुपक्षीय प्रभाव का सक्रिय रूप से विस्तार किया है। ये प्रयास न केवल विकास वित्तपोषण के विकल्प प्रदान करते हैं, बल्कि वैश्विक शासन को अमेरिका के प्रभुत्व वाले मॉडल से अलग करने का भी प्रयास करते हैं (Callahan, 2016)। जवाब में, अमेरिका ने क्वाड (जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) जैसी साझेदारियों को फिर से मजबूत किया है और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) जैसे ढांचे को बढ़ावा दिया है (Medcalf, 2020)।

कूटनीतिक रूप से, दोनों शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा विश्वदृष्टिकोणों के टकराव को भी दर्शाती है - चीन बहुध्रुवीयता और "जीत-जीत सहयोग" को बढ़ावा देता है जबकि अमेरिका पारदर्शिता, कानून के शासन और मानवाधिकारों पर जोर देता है। यह मानक विचलन तीसरे देशों के साथ उनके जुड़ाव को आकार देता है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जहां दोनों राष्ट्र रणनीतिक सहयोगियों और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक व्यवस्था के प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण दृष्टिकोण के कारण बहुपक्षीय तनाव गहरा गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार और महामारी जैसी साझा वैश्विक चुनौतियों पर भी सहयोग जटिल हो गया है।

7. भविष्य की संभावनाएँ: संघर्ष या सहयोग?

अमेरिका-चीन संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, जो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और व्यावहारिक सहयोग के ध्रुवों के बीच झूल रहा है। जबकि रिश्ते के संरचनात्मक आधार- सत्ता परिवर्तन की गतिशीलता, वैचारिक मतभेद और सुरक्षा दुविधाएँ- तीव्र प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की संभावना का सुझाव देते हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक परस्पर निर्भरता और साझा वैश्विक चुनौतियाँ निरंतर संवाद और सहयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं (Allison, 2017)।

थ्यूसीडाइड्स ट्रैप, उभरती हुई शक्तियों द्वारा स्थापित शक्तियों के साथ टकराव की ऐतिहासिक प्रवृत्ति की चेतावनी देता है। दक्षिण चीन सागर, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में चीन के तेजी से बढ़ते और मुखर व्यवहार ने अमेरिका की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे रणनीतिक गलत अनुमान या वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है (Allison, 2017)। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य घटनाएँ, ताइवान पर कूटनीतिक गतिरोध और दोनों पक्षों की ओर से बढ़ते रक्षा खर्च ने संभावित टकराव के बारे में अटकलों को और हवा दी है (Mastro, 2019)।

हालाँकि, विशुद्ध रूप से संघर्ष-उन्मुख दृष्टिकोण आपसी हितों के क्षेत्रों को नज़रअंदाज़ करता है। जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता वैश्विक मुद्दे हैं जिन्हें कोई भी देश अकेले नहीं सुलझा सकता। जैसा कि COP26 शिखर सम्मेलन में उनकी संयुक्त प्रतिबद्धताओं और ईरान परमाणु समझौते पर पिछले सहयोग से स्पष्ट है, व्यापक प्रतिस्पर्धा के बीच भी मुद्दा-आधारित सहयोग संभव है (Zhang, 2022)।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक वास्तविकताएँ कुल वियोजन पर बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। चल रहे व्यापार युद्धों और प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। गहरे वाणिज्यिक संबंध और आपस में जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाएँ, विशेष रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दुर्लभ

पृथ्वी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में, पूर्ण आर्थिक विघटन के लिए निवारक के रूप में कार्य करती हैं (Dollar & Yao, 2021)।

"प्रबंधित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा" के ढांचे का समर्थन करते हैं, जिसमें दोनों देश अपनी प्रतिद्वंद्विता को पहचानते हैं लेकिन सहयोग के अवसरों को संरक्षित करते हुए खुले संघर्ष के जोखिमों को कम करने के लिए तंत्र की तलाश करते हैं (Campbell & Doshi, 2020)। इसमें संचार की स्पष्ट रेखाएँ स्थापित करना, इंडो-पैसिफिक में विश्वास-निर्माण उपाय विकसित करना और दोनों शक्तियों को समायोजित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार करना शामिल है।

वैचारिक विभाजन संभवतः तनाव का एक निरंतर स्रोत बना रहेगा। हालाँकि, भविष्य के संबंध केवल वैचारिक लड़ाइयों से परिभाषित नहीं हो सकते हैं, बल्कि इस बात से परिभाषित होंगे कि प्रत्येक पक्ष इस जटिल परस्पर निर्भरता को कैसे व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाता है और तनाव को बढ़ने से रोकता है।

8. निष्कर्ष

21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंध वैश्विक राजनीति में सबसे अधिक परिभाषित और जटिल द्विपक्षीय गतिशीलता में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य शक्तियों के रूप में, उनकी बातचीत न केवल इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समग्र प्रक्षेपवक्र को भी प्रभावित करती है। इस शोध से पता चला है कि अमेरिका-चीन संबंध सतर्क जुड़ाव और आर्थिक परस्पर निर्भरता से विकसित होकर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सैन्य प्रतिस्पर्धा और वैचारिक मतभेदों की विशेषता वाले अधिक टकराव वाले रुख में बदल गए हैं।

ऐतिहासिक रूप से, व्यापार, कूटनीति और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में सहयोग के चरण स्पष्ट रहे हैं। हालाँकि, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, प्रौद्योगिकी नेतृत्व और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर बढ़ते तनाव ने अविश्वास को और गहरा कर दिया है। संबंधों की वर्तमान स्थिति को "प्रतिस्पर्धी अंतरनिर्भरता" के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है - जहाँ प्रतिद्वंद्विता महामारी, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता के साथ सह-अस्तित्व में है।

बढ़ते टकराव के बावजूद, प्रत्यक्ष टकराव अपरिहार्य नहीं है। दोनों देशों के पास खुले संघर्ष से बचने के लिए मजबूत प्रोत्साहन हैं क्योंकि इससे विनाशकारी आर्थिक और सुरक्षा परिणाम सामने आएंगे। अमेरिका-चीन संबंधों का भविष्य दोनों शक्तियों की अपने मतभेदों को प्रबंधित करने, रणनीतिक विश्वास स्थापित करने और रचनात्मक कूटनीति में संलग्न होने की क्षमता पर निर्भर करेगा। "प्रबंधित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा" की अवधारणा इस तेजी से बहुध्रुवीय और विवादित वैश्विक वातावरण को नेविगेट करने के लिए एक यथार्थवादी रूपरेखा प्रदान करती है।

निष्कर्ष के तौर पर, अमेरिका-चीन संबंध तनावपूर्ण और बहुआयामी बने रहने की संभावना है, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों की विशेषता होगी। दोनों देशों और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिस्पर्धा खुले टकराव में न बदल जाए, और जहाँ संभव हो, वैश्विक शांति और स्थिरता के हित में सहयोग किया जाए।

संदर्भ

- Allison, G. (2017). *Destined for war: Can America and China escape Thucydides's trap?* Houghton Mifflin Harcourt.
- Allen, G. C. (2019). *Understanding China's AI strategy: Clues to Chinese strategic thinking on artificial intelligence and national security*. Center for a New American Security (CNAS). <https://www.cnas.org/publications/reports/understanding-chinas-ai-strategy>
- Bown, C. P., & Kolb, M. (2021). *Trump's trade war timeline: An up-to-date guide*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide>
- Bown, C. P. (2020). *US-China trade war tariffs: An up-to-date chart*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>
- Buszynski, L., & Sazlan, I. (2007). Maritime claims and energy cooperation in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 29(1), 143–171. <https://doi.org/10.1355/CS29-1H>
- Callahan, W. A. (2016). China dreams, China's rise and the world order. *Globalizations*, 13(1), 10–25. <https://doi.org/10.1080/14747731.2015.1050196>
- Campbell, K. M., & Doshi, R. (2020). How America can shore up Asian order: A strategy for restoring balance and legitimacy. *Foreign Affairs*, 99(5), 14–20. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-04/how-america-can-shore-asian-order>
- Dollar, D., & Yao, Y. (2021). *U.S.-China economic relations: From confrontation to strategic competition*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/research/u-s-china-economic-relations-from-confrontation-to-strategic-competition/>

- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). *Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion*. *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
- Friedberg, A. L. (2018). *Competing with China*. *Survival*, 60(3), 7–64. <https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1470755>
- Friedberg, A. L. (2011). *A contest for supremacy: China, America, and the struggle for mastery in Asia*. W. W. Norton & Company.
- Glaser, B. S. (2021). U.S.-Taiwan relations and the threat of conflict with China. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/report/us-taiwan-relations-and-threat-conflict-china>
- He, L. (2021). Understanding China's "dual circulation" strategy: Background and implications. *China Economic Review*, 68, 101629. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101629>
- Kickbusch, I., & Liu, A. (2020). The global health governance power shift: China and the USA in the WHO. *BMJ Global Health*, 5(4), e002627. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002627>
- Kissinger, H. (2011). *On China*. Penguin Press.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific*. Random House.
- Kania, E. B., & Weber, E. (2020). *China's push to shape the future of global tech standards*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/techstream/chinas-push-to-shape-the-future-of-global-tech-standards/>
- Lee, J., & Triolo, P. (2020). *Navigating the U.S.-China tech war: A strategic framework*. Eurasia Group. <https://www.eurasiagroup.net/live-post/navigating-the-us-china-tech-war>
- Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific empire: China, America and the contest for the world's pivotal region*. Manchester University Press.
- Mastro, O. S. (2019). The stealth superpower: How China hid its global ambitions. *Foreign Affairs*, 98(1), 31–39. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-01-01/stealth-superpower>

- Morrison, W. M. (2019). *China-U.S. trade issues* (CRS Report No. RL33536). Congressional Research Service. <https://sgp.fas.org/crs/row/RL33536.pdf>
- Office of the United States Trade Representative (USTR). (2020). *Economic and trade agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of China: Phase One deal*. https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/phase_one_agreement-English.pdf
- Office of the Secretary of Defense. (2023). *Military and security developments involving the People's Republic of China 2023: Annual report to Congress*. <https://media.defense.gov>
- Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). *Exporting digital authoritarianism: The Russian and Chinese models*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/exporting-digital-authoritarianism/>
- Rolland, N. (2020). *China's vision for a new world order*. The National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/chinas-vision-for-a-new-world-order/>
- Rühlig, T. N. (2020). *The EU's 5G network security: A techno-geopolitical tightrope act*. *China Monitor*, 69, 1–12. <https://www.merics.org/en/report/eus-5g-network-security-techno-geopolitical-tightrope-act>
- Segal, A. (2020). *The coming tech cold war with China*. *Foreign Affairs*, 99(4), 10–18.
- Suzuki, S. (2022). China's approach to international institutions: Soft balancing with revisionist intent. *International Affairs*, 98(1), 53–71. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab203>
- Shambaugh, D. (2013). *China goes global: The partial power*. Oxford University Press.
- Wang, J. (2021). Strategic competition and the transformation of U.S.-China relations. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.1142/S237774002150001X>
- White, H. (2012). *The China choice: Why we should share power*. Oxford University Press.



- White House. (2021). *Interim National Security Strategic Guidance*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/>
- Zhang, Z. (2022). Climate cooperation in U.S.-China relations: Opportunities and constraints. *Global Environmental Politics*, 22(1), 115–132. https://doi.org/10.1162/glep_a_00601